


केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील)	
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, 4 th Floor, Central Excise Building, Near Polytechnic, सातवीं मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	
079-26305065	टेलिफैक्स : 079 - 26305136

रजिस्टर डाक ए.डी.द्वारा

क फाइल संख्या (File No.): V2(ST)278/A-II/2016-17 / 10231 - 10 10235
स्थगन आवेदन संख्या (Stay App. No.):
ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): AHM-EXCUS-002-APP-123-17-18
दिनांक (Date): 27/10/2017, जारी करने की तारीख (Date of issue): _____
श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील-II) द्वारा पारित
Passed by Shri Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग _____ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-IV), अहमदाबाद, आयुक्तालय द्वारा जारी
मूल आदेश सं-_____ दिनांक _____ से सृजित
Arising out of Order-In-Original No. _SD-04/REF-68/AK/2016-17_ Dated: 05.01.2017
issued by: Assistant Commr STC(Div-IV), Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s Devjeet Construction Co..

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India:

(1) (क) (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

Cont...2

- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हों।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इ.ए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनोंक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मेटल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग" (Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो मांग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER IN APPEAL

M/s. Devjeet Construction Co. (*hereinafter referred to as 'appellant'*), situated at "SAHDEV" 18, Yogikrupa Society, Barwala Highway Road, Dhandhuka, Ahmedabad-382460, holding Service Tax Registration No. AEGPS6761QSD001 for providing Works Contract Service, Construction of Residential Complex Service, Construction Services other than residential complex, including commercial/industrial building or civil structure and Legal Consultancy Service, have filed the present appeal on 07.03.2017, against the Order-in-Original number SD-04/REF-68/AK/2016-17 dated 05.01.2017 (*hereinafter referred to as 'impugned order'*) passed by the Assistant Commissioner, Service Tax, Division-IV, Ahmedabad (*hereinafter referred to as 'adjudicating authority'*), rejecting the appellant's refund claim of Rs.5,19,575/-, on the grounds of unjust enrichment.

2. The facts of the case, in brief, are that the appellant's tender for construction of a Community Hall at Barwala was accepted by Barwala Nagar Palika and for construction of Judicial Staff Quarters at Vijaynagar, (Dist. S.K.) was accepted by the Executive Engineer, R&B Division, Himmatnagar (Dist. S.K.) . The contracts awarded to the appellant were for a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry or any other business or profession, by the government. Vide Notification No. 06/2015-ST dtd.01.03.2015, the service provided to the Government was made taxable w.e.f. 01.04.2015, and therefore the appellant started paying Service Tax. However, vide entry No. 1(iv) of the Notification No. 09/2016-ST dated 01.03.2016, the Notification No. 25/2012-ST was amended, as indicated below :

"after entry 12, with effect from the 1st March, 2016, the following entry shall be inserted, namely -

"12A. Services provided to the Government, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of -

(b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment, under a contract which had been entered into prior to the 1st March, 2015 and on which appropriate stamp duty, where applicable, had been paid prior to such date."

Accordingly, in view of this amendment, the appellant had sought the refund of Rs.5,19,575/-, paid by them. The Adjudicating authority vide impugned order sanctioned the Refund claim amount of Rs. 5,09,897/-, but ordered to credit the said amount to the Consumer Welfare Fund and rejected the refund claim of a total amount of Rs. 9,678/-, which included Rs.950/-,

being interest on delayed payment of Service tax and Rs.8,728/-, being Swachh Bharat Cess.

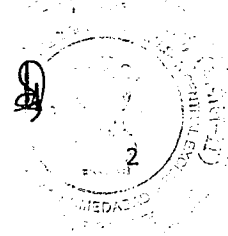
3. The appellant being aggrieved by the impugned order filed this appeal on the grounds that (i) the adjudicating authority rejected the refund application without following the principles of natural justice; (ii) the doctrine of unjust enrichment is not applicable in this case; (iii) the refund of interest paid on delayed payment of service tax is eligible to them; (iv) the refund of Swachh Bharat Cess is eligible to them; and (v) interest is payable to them for the delay beyond the prescribed time limit for sanctioning refund.

4. During the personal hearing, the appellant's authorized Chartered Accountant appeared before me. They reiterated the grounds of appeal and submitted a certificate from the Barwala Nagarpalika regarding non-payment of Service tax to the appellant with regard to the construction work of Community Hall.

5. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of appeal in the Appeal Memorandum and oral submissions made by the appellants at the time of personal hearing.

6. The question to be decided is as to whether (i) unjust enrichment is applicable in this claim; (ii) the refund of interest on delayed payment of service tax and Swachh Bharat Cess, has be rightly rejected; (iii) the principles of natural justice have been flouted by the adjudicating authority; and (iv) interest is payable to the appellant for the delay in sanctioning refund.

7. I find that the issue of admissibility of refund has already been agreed by the adjudicating authority. As regards the applicability of unjust enrichment in this refund claim, the appellant has to provide all the documentary evidence in this regard before the adjudicating authority to arrive at a conclusion in this matter, to the satisfaction of the adjudicating authority. The appellant's contention that a hearing had not been given to them before rejecting the refund claim by the adjudicating authority is an absolute denial of natural justice to the appellant. As regards the rejection of refund in the impugned order of Rs. 950/-, being interest paid for delayed payment of service tax is clearly and comprehensively covered in Section 11B of the Central Excise Act, 1944, and hence is set aside to that extent. As regards the rejection of refund in the impugned order of Rs. 8,728/-, being Swachh Bharat Cess, the sub-section (5) of Section 119 of Chapter VI of the Finance Act, 2015, states that -



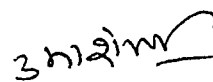
"(5) The provisions of Chapter V of the Finance Act, 1994 and the rules made thereunder, including those relating to refunds and exemptions from tax, interest and imposition of penalty shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the Swachh Bharat Cess on taxable services, as they apply in relation to the levy and collection of tax on such taxable services under Chapter V of the Finance Act, 1994 or the rules made thereunder, as the case may be."

Thus, it is amply clear that refund of Swachh Bharat Cess has to be sanctioned in the light of the above provisions. In the light of the above, the entire refund claim of Rs. 5,19,575/-, is admissible, subject to the applicability of unjust enrichment, which is to be decided by the adjudicating authority based on the documentary evidence produced before him by the appellants.

8. I, therefore, remand back the refund claim to the adjudicating authority to decide the matter of unjust enrichment with regard to the entire claim of Rs. 5,19,575/-, after seeking documentary evidence from the appellants and also giving them a personal hearing.

9. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The appeal filed by the appellant, stands disposed off in above terms.



(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स)

ATTESTED



(R.R. NATHAN)
SUPERINTENDENT,
CENTRAL TAX APPEALS, AHMEDABAD.
To,

M/s. Devjeet Construction,
'Sahdev', 18 , Yogi Krupa Society,
Barwala Highway Road,
Dhandhuka,
Ahmedabad-380015.

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, Central Tax, GST, Ahmedabad Zone.
- 2) The Commissioner, Central Tax, Ahmedabad-North.
- 3) The Dy./Asst. Commissioner, Division-V, Central Tax, GST, Ahmedabad (North), Ahmedabad.
- 4) The Asst. Commissioner(System), Central Tax, Hqrs., Ahmedabad (North).
- 5) Guard File.
- 6) P.A. File.

